



आरत का राजपत्र

The Gazette of India

प्रधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 31, 1998 (कार्तिक ९, 1920)
No. 44] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 31, 1998 (KARTIKA ९, 1920)

(इस साग में इन पाँडि संख्याएँ दर्शाई हैं जिन्हें कि यह सभी दस्तावेज़ के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part so that it may be filed as a separate compilation.)

भाग III—भाग 4
(PART III—SECTION 4)

[अनियुक्त विज्ञापनों द्वारा जारी की गई विविध अधिकृदानाएँ जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएँ समितित हैं]

(Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies).

आरतीय चार्टर्ड आक्ट सेक्वेकार संस्थान

मुख्य-400008, दिल्ली २७ भारत १९९८

सं. ३ उल्लंशीए (६) ९/९७-९८—चार्टर्ड आक्ट सेक्वेकार विनियम १९८८ के विनियम १०-१ वाले ३ के अनुसरण में एतद्वारा यह सुनित किया जाता है कि नियन्त्रित संस्थाओं को जारी किए एवं प्रेक्षित प्रमाण-पत्र को उनके बावें वी पर्ह तिथि से रह कर दिया गया है व्यवोंकि वे अपने प्रमाण-पत्र को रखने के इच्छुक नहीं हैं:-

सं. सं.	संस्थाना सं.	नाम एवं पता	दिनांक
१	२	३	४
१. ००३९७१		श्री पटेल श्रीकाला चतुरमार्य, ए०५००५०, २८, श्री किंग्स, एस० बी० रोड, दिल्ली नाफ दरोदा के ऊपर, सोनामूर्ज—सिल्वर, मुख्य-400054।	०५-०३-९८

१०. पीढ़ि किसी कारणबद्ध स्थापना के क्रमसंचारी भारतीय औद्योगिक विनायक की उत्तराधिकारी को एक स्कॉप के चिह्न स्थापना पहले अपना चुकी है जबकि नहीं रह जाता है या इस स्कॉप के बचीत कमज़ोरी द्वारा को प्राप्त होने वाली विनायक किसी राशि से कम हो जाए है स्कॉप रद्द की जा सकती है।

१० यदि लिसी कारणवश नियोजन के उद्द निवारणार्थीका
प्रतीक की वीक्षण शीर्ष किए गए विषय कर्ता प्रतीकादाम का संचाय करने
का असम्भव अस्तु तो शीर्ष प्रतीकार्थी को बहाल होने दिया जाय।

१३८ निवासकः द्वारा भौमिकम् के संबोध हैं कि ए गए किसी आर्थिक कार्य की वाहन को उत्तम स्वरूप में बदल निवासियों द्वा लिया जाए, जिससे लोगों द्वारा यह बाटने द्वारा गाँड़ छुटी तो उससे स्कौल के अद्यार्थ होते, तथा इन्होंने संबोध का व्रत द्वारा विषय निवासक पर होता।

१९०) इकलौ स्थापना के हमें नहीं मिलता है वह गवाह जो अधीन भासी गया है। इसी उद्देश्य की वज्र और पर बातों के अन्तर्मान विद्यमानों/डिजिटल हार्डिंगों को बीमारत राशि का संबंध गढ़ते हुए एवं विवरण इकलौ स्थापना वाले भागीदार जीव बीमार जिग्नाम हैं दीपांगल राशि वाले हुए को एक स्थापना के भीतर सम्बद्ध करना।

मिशनरीज नेपाली भाषा में लिखा है। जी. डी. राण्डे
मिशनरीज नेपाली भाषा में लिखा है।

भारतीय इन्स्ट्रुमेंट परिषद

सं० ई० ई० 22-98—दस्त परिवर्त अधिनियम 1848
 (1848 का 16) की भारा 20 के बाल (ग) के अंतर्गत
 असत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दस्त परिवर्त
 अधिनियम सरकार के अनुबोदन से, एसडूँडारा दस्त कालेजों में
 अध्योदित प्रवेश क्षमता से अतिरिक्त वाहिल किए गए छात्रों
 की प्राप्ति करने के लिए चिन्मलिकिल दिनियम बनाती है,

- (1) संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :— इन विनियमों को भारतीय दल परिषद् (दल कालेजों में प्रवेश अमता के अतिरिक्त डाक्टिल किए गए छात्रों की पहचान के मानदण्ड) विनियम, 1998 कहा जाएगा।
 - (2) ये तरकारी राशियाँ में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्त्त होंगी।

2. प्रयोगशीलता :— ये विनियम उन सभी दस्त कालेजों
संस्थाओं/विश्वविद्यालयों पर लागू होंगे जो स्नातकपूर्वी/स्नातकोत्तर
दस्त पास्क्रिप्टों का आधोरण करते हैं (जिन्हें एतदप्रथामा
“दस्त कालेज” कहा गया है)।

A-309 GI/98

3. परिभ्रान्त :—इन विनियमों में, जब तक संवर्ध से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से भारतीय दल परिषद् अधिनियम 1948 (1948 का 16) अधिसूचना है।

(क) "प्रबोध अवस्था" का वही अर्थ है जिसकि अधि-
नियम की आमता 10-के संसदीयकरण 2 में
दिया गया है।

(ग) "सत्ताने प्राधिकारी" से केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अपने कोई लोअर प्राधिकारी बनिश्वेत है जिसे केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार जैसा भी मानता हो, इतर प्राधिकारी राज्य अथवा संघ राज्य लेवल में विभिन्न रूप कालेजों में प्रवेश के लिए छात्रों का आवंटन करने के लिए नियुक्त किया गया हो।

(४) सभी अन्य शब्दों और अविवाहित शब्दों का वही अध्य होणा जैसा कि अधिनियम में परिचालित किया गया है।

४. इन्हे कालेज में स्वीकृत प्रवेश भवता:— परिषद्
प्रत्येक बर्द, स्नातकपूर्वस्नातकोत्तर विविध दस्त
पाठ्यक्रम के बहु होने से पहले, इन्हे कालेजों और
राज्यसंघ राज्य क्षेत्र की उत्कार्तों को दस्त कालेजों
में स्नातकपूर्वस्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों की
स्वीकृत प्रवेश भवता दिवित करेगी। १३८ नं। १३८

५. इन्हे छात्रों द्वारा छात्रों की बर्च-बार तभी भवता—

(1) स्नातकपूर्वस्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का अप्रोजेशन करने वाले सभी बच्चे कालेज, इन विनियमों के सरकारी राज्यपाल में प्रकाशित होते के तीन महीनों के भीतर, इन शब्द विनियम स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के सामग्री में (प्रथेक पाठ्यक्रम के लिए अलग-अलग) वर्ष 1992 में शुरू हुए वीजिक सर्वों से लेकर जिस वर्ष ये विनियम प्रकाशित होते हैं उस वर्ष तक के वीजिक सर्वों के द्वारा यादित किए गए छात्रों की वर्ष-वार मुद्रितों परिवर्त को सेवने।

(2) दन्त कालेज, दन्त शल्प चिकित्सा स्नातक और स्नातकोत्तर पाद्यक्रमों के लिए प्रथमेक शैक्षिक वर्ष के द्वितीय वार्षिक एवं छात्रों की सूची, वार्षिक बन्द होने के 15 दिन के भोतर अवधा उस शैक्षिक वर्ष के 15 अक्टूबर तक, जो भी पहले हो, सभी प्राधिकारी को भेजेंगे और उसकी एक प्रतिलिपि परिवद्वारा को भेजेंगे।

6. समस्या प्राचिकारी द्वारा - सूची भेजना :— समस्या प्राचिकारी, इन्हे शब्द विकित्सा स्नातक और स्नातकों तर पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के द्वारा दाखिल किए गए छात्रों की सूचियाँ, इन्हे कालिजों

3

से सुखाया गया होते के 1.5 दिन के भीतर, अब वह
उस वर्ष 31 अक्टूबर तक, जो भी पहुँच हो, परिवद्ध
राज्य है। परिवद्ध और सम्बद्ध विवरिकालम को
भेजेगा।

३. परिषद् को भेजी जाने वाली आक्रों की सूची:-

- (1) इन विविधतों के अन्तर्गत परिषद् को भेजी जाने वाली छात्रों की सुनी -समझ आधिकारी द्वारा सुनी "मेरिट" का के अनुसार उत्त्यार की जाएगी जिसके आधार पर दाखिला दिया गया है।
 - (2). सुनी के साथ दस्तावेज़ का डील/प्राप्तानामांश में एक बच्चवडहाटा भी भेजेगा जिसमें उस दस्तावेज़ की स्वीकृत प्रवेश अवस्था का उल्लेख करने के साथ-साथ इस दाता का भी उल्लेख करेगा कि स्वीकृत प्रवेश अवस्था से अतिरिक्त छात्रों/छात्राओं को दाखिला नहीं दिया गया है।
 - (3) दस्तावेज़ में धर्मिता भारतीय प्रवेश परीक्षा/केन्द्रीय पूर्व कोड़ा/अनुबृतित जातियों/अनुबृतित जनजातियों के लिए आवापक आरक्षण के धार्मिक से धार्मिक किए जए छात्रों/छात्राओं के नामों का उल्लेख भी सुनी में होता।

८. स्वीकृत प्रदेश अमरतः से अस्तिरिक्त वाचिकाने संबंधित ग्रामों पर किसी परिवह द्वारा लिया जाए :—

- (1) सम्प्राप्तिकारी द्वारा परिषद् को भेजी गई दूषी बोरदाट कारेच के लिए निर्वाचित प्रवेश असता की घटाव में रखते हुए उत्तिष्ठित शाखिल किए गए छात्रों के संघर्षित सभी शास्त्रों परिषद् द्वारा निर्वाचित दिए जाएंगे।

रियू, यह पारी है कि स्त्रीहत प्रवेश
के अतिरिक्त वाहिने दिए जाए हैं तो
वीने के लालों की स्त्रीहत प्रवेश नहीं।
अतिरिक्त वाहिने बाधा !

भारतीय प्रवेश परीक्षा/किलोमीटर प्रूफ
पुस्तकित भारतीयों/जन वासियों भारत
के लिए आगामी भारतीय के मान्यता से उद्दिष्ट
किए यह लाइट की नियमित प्रवेश भवनों के
भीतर वासियों किटा जाएगा।

१०. अलेंड्रिस दाखिलों की पहचान और उन्हें अद्वितीया को
संप्रभावित करने की क्षमता।

- (1) परिवद्ध किसी भी दृष्टि कालेज में अतिरिक्त शाखाओं का पाठ नामायनी और अतिरिक्त प्रोफेस के अनुसार आगे बासे दृष्टि कालेज के पृष्ठान किए दृष्टि किसी भी छात्र को इनमें की वह दृष्टि असुविधा, अविभिन्नता के प्रयोगका के किए भास्तवा प्राप्त दृष्टि अहसा नहीं होती। ऐसे पृष्ठान किए यह छात्रों के नाम और वह ज्ञानी, अधिनियम के उपर जीवों के अवीन कायेंद्राही किए जाने के लिए, परिवद्ध दृष्टि सभी तथ्यान्वय को सूचित किए जाएं।

(2) किसी इन कालेज में छात्रों को अतिरिक्त शाखाएँ भी पृष्ठान के नामकों में किसी भी विवाद को लिये के लिए केत्रीय सरकार को भेजा जाएगा।

(का० सं० शी०-12025/19/98-शी०एम० एस०)

ए० एम० मिशनी
संस्कृत
शास्त्रीय वक्ता पदिक

ब्राह्मण नं ४७ १९३६-७

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and whenever an amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, of the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium, the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

K. C. PANDEY
Regional Provident Fund Commissioner

DENTAL COUNCIL OF INDIA

No. DE-22-98.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of section 20 of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948), the Dental Council of India, with the approval of the Central Government, hereby makes the following regulations relating to identification of students admitted in excess of the approved admission capacity of Dental Colleges, namely:—

1. (1) Short title and commencement: These regulations may be called the Dental Council of India (Criteria for identification of students admitted in excess of admission capacity of Dental Colleges) Regulations, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application:—These regulations shall apply to all dental colleges/institutions/universities conducting undergraduate/post-graduate dental courses (hereinafter referred to as the dental colleges).

3. Definitions:—In these regulations unless the context otherwise requires:

(a) "Act" means the Dentists Act, 1948 (16 of 1948);

(b) "Admission capacity" has the same meaning as in Explanation 2 of Section 10-A of the Act.

(c) "Competent Authority" means the Central Government or the State Government or any other authority as may be designated by the Central Government or the State Government as the case may be to allot students for admission to various dental colleges in a State or Union territory.

(d) All other words and expressions shall have the same meaning as defined in the Act.

4. Sanctioned intake capacity in dental colleges:—The Council shall every year, prior to the start of undergraduate/post-graduate academic dental course, intimate the dental colleges and State/Union territory Governments, the sanctioned intake capacity of students for undergraduate/post-graduate courses in dental colleges.

5. Dental Colleges to furnish year-wise list of students:—

(1) All dental colleges conducting undergraduate/post-graduate course shall, within three months of publication of these regulations in the Official Gazette, furnish year-wise lists of students admitted during the academic sessions commencing in the year 1992 till the year in which these regulations are published, for Bachelor of Dental Surgery and post-graduate course (for each course separately) to the Council.

(2) The dental colleges shall furnish to the Competent Authority the list of students admitted during each academic year for Bachelor of Dental Surgery and Post-graduate courses, with a copy endorsed to the Council within fifteen days of the closure of admissions or 15th October of that academic year, whichever is earlier.

6. Furnishing of List by Competent Authority:—Competent Authority shall furnish lists of students admitted during each

(5)

academic year for Bachelor of Dental Surgery and post-graduate courses to the Council, the State Dental Council and the affiliating University, within fifteen days of the receipt of information from dental colleges or by 31st October of that year whichever is earlier.

7. List of students to be furnished to the Council

- (1) A list of students to be furnished under these regulations to the Council shall be prepared by the Competent Authority in order of merit on the basis of which admissions have been made.
- (2) The list shall be supported by undertaking of the Dean/Principal of a dental college stating the sanctioned admission capacity of that dental college and that no admission has been made in excess of the sanctioned admission capacity.

(3) The names of students admitted in a dental college through all India Entrance Examination/Central Pool quota/mandatory reservation for the Scheduled Castes/Scheduled Tribes shall find mention in the list.

8. Matters relating to excess admission to be decided by the Council

(1) All matters relating to excess admission of students shall be decided by the Council taking into account the list furnished to the Council by a Competent Authority and the admission capacity fixed for the dental college.

(2) If the Council finds that the admissions have been made over and above the sanctioned admission capacity, the students lower down in the list shall be treated to be admitted in excess of the sanctioned admission capacity.

(3) The students admitted through All India Entrance Examination/Central Pool Quota/mandatory reservation for the scheduled Castes/Scheduled Tribes, etc. shall be included within the fixed admission capacity.

9. Identification of excess admission and non-recognition of dental qualification

(1) The Council shall find out the excess admissions in a dental college and no dental qualification granted to any identified student of the dental college which comes under the excess admission shall be recognised dental qualification for the purpose of the Act. The names and other particulars of students so identified shall be intimated by the Council to all concerned for taking action under the provisions of the Act.

(2) Any dispute in the matter of identification of excess admission of student(s) in a dental college shall be referred to the Central Government for decision.

F. No. V. 12025/19/96-PMS

A.L. MIGLANI
Secretary
Dental Council of India.